



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष 1938 (श10)

(सं० पटना 30) पटना, बृहस्पतिवार, 12 जनवरी 2017

सं० 08/आरोप-01-100/2015-13884 सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

7 अक्टूबर 2016

श्री पवन कुमार मंडल, बि०प्र०से०, कोटी क्रमांक-1181/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने का आरोप राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-10290, दिनांक 21.08.2015 द्वारा प्राप्त हुआ जो आयोग में संस्थित वाद सं० 88434/12-13 श्री वीरेन्द्र महतो बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी के मामले में दिनांक 03.08.2015 को पारित आदेश के अनुपालन से आच्छादित था।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक-13873, दिनांक 14.09.2015 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण मांगा गया। इस क्रम में श्री मंडल का स्पष्टीकरण (पत्रांक-1856, दिनांक 23.09.2015) प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वयं को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया।

विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' एवं श्री मंडल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के पद पर दिनांक 12.04.2013 से दिनांक 16.07.2014 तक पदस्थापित रहे। इस अवधि में दिनांक 26.12.2013 को आवेदक श्री वीरेन्द्र महतो द्वारा राज्य सूचना आयोग में दायर अपील में पारित आदेश उनके संज्ञान में आया। उन्होंने दिनांक 26.12.2013 को ही लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर को दिनांक 02.01.2014 तक आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया। इसके साथ ही स्वयं के स्तर पर उक्त मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित विभिन्न तिथियों पर संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा तथा अन्ततः मामले को निष्पादित कर दिया। इस सब के बावजूद आरोपित पदाधिकारी के कार्यकाल तक आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 03.08.2015 को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विरुद्ध कार्यवाई की अनुशंसा करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सूचना पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी श्री मंडल के अधीनस्थ पदाधिकारी थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यदि श्री मंडल अपने स्तर से समुचित कार्यवाई करते तो आवेदक को ससमय सूचना प्राप्त हो जाती परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस आधार सूचना का

अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में इनकी उदासीनता एवं कर्तव्यहीनता प्रमाणित होती है तथा इस आलोक में श्री मंडल का स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री पवन कुमार मंडल, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1121/11 को “चेतावनी” संसूचित की जाती है जो उनके चारित्री पुस्त में दर्ज की जायेगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 30-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>